12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED WARNING BY BHAKRA MANAGEMENT BOARD TO DISCONTINUE POWER SUPPLY TO DESU

श्री हुकमचन्द कछवाय (मुरेना) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न-लिखित विषय की ओर सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :—

'दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम द्वारा बकाया राशि न चुकाई जाने के कारण भाखडा प्रबन्ध बोर्ड द्वारा इस उपक्रम को बिजली की सप्लाई बन्द किए जाने का समाचार।"

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, भाखडा प्रबंध बोर्ड से करार के प्रारूप के आधार पर अप्रैल 1955 से विद्युत लेता जा रहा है। तब से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और भाखडा प्रबन्ध बोर्ड के बीच इस संबंध में एक विवाद चला आ रहा है कि दिल्ली विद्युत प्रदान संस्थान भाखड़ा से कितनी मात्रा में विद्युत लेने का हकदार है और संशोधित कर किस तारीख से लागू की जानी है। ऐसे कई अवसर आए हैं जब दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अपनी खरीद में कटौती कर और अपनी ताप प्रणाली से विद्युत देकर दोनों ही तरह से भाखडा प्रणाली की सहायता की थी। भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से लगभग 6.5 करोड़ रुपये की बकाया राशि की अदायगी का दावा किया है। दोनों ही पक्षों ने पन्द्रह दिन पहले सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से विवाद का अन्त करने में सहायता करने का प्रस्ताव किया है। विद्युत सप्लाई को बन्द करने का कोई भी नोटिस दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को नहीं भेजा गया है। जब तक इस मामले का निपटान नहीं हो जाता, भाखड़ा से दिल्ली को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई बन्द नहीं की जाएगी।

श्री हुकमचन्द कछवाय : माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें बहुत सी बातें उन्होंने नहीं कही है। यह भाखड़ा बिजली बोर्ड द्वारा जो कुछ दाम बढ़ाये गए हैं बिजली के उसके कारण इतनी अधिक धनराशि उनकी हुई है। वह दावा कर रहे है कि वह धनराशि उन्हें अर्थात् दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को देनी चाहिए। उन्होंने केन्द्र सरकार को लिखा है। लेकिन केन्द्र सरकार ने इस बारे मे बिल्कुल विचार नही किया और न इस सम्बन्ध मे कोई उत्तर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि यह मामला अनेक दिनों से खटाई में पड़ा हुआ है और केन्द्र सरकार इस को सुलझाने में अब तक असमर्थ है। क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय सरकार को भी इस बात का पता है कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के ऊपर भी डी० ई० एस० यू० की बडी रकम बकाया है और वह रकम नही दे रही है। क्या इसकी जानकारी आपको है, और वह पैसा भी आप दिलवायेंगे।

साथ ही साथ दिल्ली भारत की राजधानी है इसके अन्दर तीन हिस्सों मे अलग-अलग रेट हैं, पुरानी दिल्ली मे अलग रेट है, नई दिल्ली में अलग रेट है और सरकारी कालोनीज के रेट अलग है। तीनो मे अन्तर है। तो यह रेट समान हो इसके लिए आप कोई प्रयास कर रहे है क्या ? करार के अनुसार 80 मेगावाट बिजली भाखडा को देनी थी और वह दे रहा है 60 मेगावाट। इस मामले को आप ने स्वीकार किया है कि बहुत दिनों से यह मामला उलझा पडा हुआ है। तो उन्हें पूरी तरह बिजली मिले उसके लिए भी आप क्या प्रयास कर रहे है।

क्या यह बात सही है कि भाखडा 7 लाख यूनिट बिजली दिल्ली को देता है लेकिन दिल्ली भी 10,12 लाख यूनिट बिजली देता रहा है। यदि भाखड़ा बिजली देना बन्द कर देगा तो दिल्ली भी उनको बिजली देना बन्द कर देगा। वैसी हालत मे क्या स्थिति होगी दोनों जगह इसका आप स्वयं अन्दाज लगा सकते है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यह मामला जल्दी से

मुलझे उसके लिए आप कौन से कदम उठा रहे है ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K L. RAO) : The information required by the hon Member has been given in the answer. The claim is to the extent of about Rs 6 5 crores ; B.M.B. say that they are entitled to get about Rs 6 5 crores from DESU and that is that they have asked for and it has not been hanging on for years. This information has been brought to our notice only a fortnight back and we have been asked to arbitrate between these two and that will be done. There is no question of any crisis. No power will be cut off to Delhi from Bhakra. That is also given in the answer.

श्री हुकमचन्द कछवाय : नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के ऊपर भी 3 करोड रु० दिल्ली प्रदाय संस्थान का बाकी है जो कि उसे लेना है । तो उन्हें पैसा दिलाया जाये उसके लिए मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा । एक सवाल और मैंने उठाया था कि दिल्ली नगर के अन्दर अलग-अलग रेट है, पुरानी दिल्ली मे कुछ, नई दिल्ली मे कुछ और सरकारी कालोनियों मे कुछ, इस अन्तर को समाप्त करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे है इसका उत्तर मन्त्री जी की ओर से नही आया ।

DR. K. L RAO : That is a separate question, Sir This question relates to alleged arrears of payment due by the DESU to the Bhakra Management Board. The hon. Member is asking about the New Delhi Municipal Committee *versus* the DLSU. The NDMC has not reported to us that any amount is due to them by the DESU. If the respective Committee writes to us, then we will take it up.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ने लीगल रेडवाइस लेने के बाद यह नोटिस सर्व कर दिया है कि दो महीने मे अगर 6 करोड 5 लाख रु० का भुगतान नहीं होगा तो तारों मे बिजली नही रहेगी । दिल्ली को बिजली सप्लाई नहीं करेंगे । आप स्वयं कह रहे है कि दोनों पार्टियां 15 दिन पहले हमारे पास आयी और आप आर्बिट्रेटर के रूप में काम करना चाहते है और फैसला देना चाहते है । तो मै जानना चाहता हूँ कि क्या डी० ई० एस० यू० और भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड, इन दोनों पार्टियों ने आपको स्वीकार कर लिया है कि आपका जो निर्णय होगा वह फाइनल होगा और दोनों पर बाईंडिंग होगा, या नहीं । जब उन्होंने पहला समझौता किया था पंजाब इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से उस समझौते से वह पाबन्द नही है, और जो टैरिफ बढ़ाया गया है—2.75 पैसे से 5 पैसे और 3.25 पैसे से 6 पैसे के हिसाब से, तो दिल्ली की डी० ई० एम० यू० कनज्यूमर से कितना लेती है और लेने के बाद वह रुपया जमा है या उन्होंने दूसरे काम में उसका उपयोग कर लिया है ? और अगर कर लिया है तो सरकार उस बारे मे क्या कदम उठा रही है । मै समझता हूँ कि दिल्ली की बिजली केवल विलासिता के लिए काम में आती है । राजस्थान के अन्दर जो लोग गहरे कुओं से पानी लेना चाहते है उनको बिजली से क्यों महरूम किया जाए ? क्योंकि भाखड़ा पर हम भी क्लेम रखते है । इसलिए इस बात पर विचार किया जाय ।

MR. SPLAKER : The question is about arrears.

DR. K. L. RAO : I can tell the hon. Member that no notice has been served by the Bhakra Management Board. That has been made clear in the answer. The Bhakra Management Board passed a resolution that they want to serve a notice. But at the same time, they passed another resolution saying that the Ministry of Irrigation and Power should be approached to settle the issue.

I can tell the hon. Member that according to the Act on the subject, the Government of India has got complete powers to direct and to see that no such cutting off can be done. There were such disputes in the past also and it was never done There is no reason why we shall anticipate any difficulty. This matter has been brought to our notice only 15 days back and we will go into it. It any case, the question of cutting the power supply to Delhi does not arise and the Government of India will see to it that such a thing does not happen.

SHRI VIKRAM MAHAJAN (Kangra) : The first resolution of the Bhakra Manage-

ment Board giving the warning that if they are not paid the arrears, the electricity supply would be cut off is a glaring instance and it is a pattern which bureaucracy has developed towards the common man. Imagine, Sir, if this resolution has been put into practice, what would have happened ? Industries would have stopped. There would have been unemployment and they have chosen the worst part of the year to pass this resolution. The hottest months—May and June—they have chosen to give this threat that 'We will cut off the supply.' This is not a solitary instance of callousness on their part. They have been following this pattern repeatedly. Since last 20 years they have not even rehabilitated the oustees from Bakra Dam. In regard to the Pong Dam, for one lakh oustees they gave assurance that they would be rehabilitated. I am giving the pattern. I am showing this is the pattern which deserves to be condemned by this House. They assured in this House that they would be rehabilitated and compensation would be given. But in fact, while such an assurance was given, their houses were flooded with water ; this is exactly the pattern which they have developed. The programme of our party is that electricity and water would be given to every householder, but the policy of the bureaucracy is like the millstone around the neck of the Prime Minister, their policy is to cut off the supply. The Prime Minister wants more industries, more employment, but the policy of the bureaucracy is just the reverse.

MR. SPEAKER : You are a lawyer coming from a distinguished family of lawyers. You should be relevant.

SHRI VIKRAM MAHAJAN : I am giving instances.

MR. SPEAKER : It should be related to the Calling Attention matter.

SHRI VIKRAM MAHAJAN : The Minister said that no notice has been given. It is a very subtle distinction which he has tried to make He has said, a resolution was passed, but no notice was given. This is a distinction without any weight, I should say It is published in every newspaper. It says : "The Bhakra Management Board has warned Delhi Electric Undertaking that if they do not pay the arrears supply will be discontinued." This has come out in every paper. Either it is true or it is not true. This has appeared in '*Hindustan Times*', in '*Statesman*' etc. If they are spreading rumours, are you going to take action against the newspapers ? What action do you intend to take if they are spreading rumours ? It is my question number one. Secondly, will you take action against those officers who did pass the resolution, stating, they will cut off water supply and all that. It is a mess which is going on in your Ministry and in this Board. Will you appoint a Parliamentary Committee to go into this matter ? I want correct and accurate answers. If you cannot follow my questions, I will repeat them if you like. I will say, it will be my pleasure to repeat them again so that you can answer it...

DR. K. L. RAO : Not necessary. As a lawyer he should know about the relevancy because what he says is out of the relevancy of the subject and he always brings in the Pong oustees and all that. That has nothing to do with this scheme. That is being settled separately. Here the question is a simple question, and that is, whether Bhakra Management Board has served a notice on the DESU or not It is a perfectly simple question and in the statement I have given the reply that no such notice has been given. Passing resolution does not mean serving a notice. A distinguished lawyer must know that because passing a resolution does not mean serving a notice. Serving a notice has got a different procedure. The Bhakra Control Board was within its rights and there is nothing wrong about it. He said about mess and so on ; I don't understand where the question of mess comes in the Ministry of Irrigation at all. I have already said that the Government of India has got power to say that no power will be cut off The answer is specific and clear. He always brings in the Pong Dam and Pong oustees ; that has nothing to do with this subject. In regard to Ukai project also one lakh of people were rehabilitated and compensated for amounts less than Rs 5 crores and in this case we were spending more than Rs. 48 crores. It is a separate question and if the hon. Member gives a separate notice, we can answer about that. But, what I wish to submit is that it should be relevant to the question.

So far as the newspapers are concerned, naturally they will try to get some information

[Dr. K. L. Rao]

and when they get it they publish it. Why should we prosecute these newspapers for that ?

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : Shri Vikram Chand Mahajan wants some litigation.

DR. K. L. RAO : There is absolutely nothing wrong in their publishing it. In fact, they have done a good duty by bringing this dispute to the notice of all. I am thankful to Shri Hukam Chand Kachwai for bringing out this point, so that I could make the position clear. I want to make it clear once again that when there are two organisations, definitely there must be differences of opinion over the rate, the amount of power to be supplied and so on, and there is nothing wrong with that. The whole procedure is completely logical, and there is nothing for me to take particular notice of in this, exept this, namely that once again, I would assure the House that Delhi power will not be cut off.

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा (नवादा) : अध्यक्ष महोदय,मंत्री महोदय ने इस बात को बतलाने की चेष्टा की कि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ने बिजली काटने का कोई नोटिस नहीं दिया है, लेकिन यह ऐक्सेप्ट किया है कि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड का 6.5 करोड़ रु० बाकी है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि यह रुपया बकाया क्यों है और इतनी राशि क्यों बाकी रह गई। जहां तक हम लोगों को जानकारी है, और मुझ को इस बात का पता है कि करारनामे के मुताबिक रेट में जो बढ़ोतरी हुई है और उसी के भुगतान में विवाद है जिसके कारण दिल्ली इलैक्ट्रिक स्टेट अन्डरटेकिंग और भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड के बीच में इस बात का निर्णय नहीं हो सका कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को कब से बढ़ोतरी के मुताबिक रुपया देना है।

मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस बात का स्पष्ट करें कि दोनों के बीच में जो रुपया देने के सम्बन्ध में विवाद है उसको हल करने में इतना विलम्ब क्यों हुआ ? मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया कि नोटिस नहीं दी गई लेकिन भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड ने संकल्प स्वीकार किया गया है कि बकाया राशि का भुगतान नहीं होगा तो बिजली की लाईन काट दी जाएगी। इस बात का कि बढ़ा कर राशि अदा की जाए। इसके माने स्पष्ट हैं कि अगर यह राशि अदा नहीं होगी तो बिजली काट दी जाएगी। माननीय मंत्री महोदय के कहने से भी वह नहीं मानेंगे, जब तक पूरी राशि का भुगतान नहीं हो जाता।

दिल्ली के अन्दर तीन तरह से बिजली सप्लाई होती है और तीनों विधियों में यहां पर गड़बड़ी होती है। मुख्य गड़बड़ी का कारण यह है कि यहां पर विभिन्न प्रकार के रेट है। विभिन्न रेटों में फर्क पड़ने के कारण एक दूसरे के साथ मतभेद है और उसी कारण से इतनी बड़ी राशि बाकी है।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वह दिल्ली में बिजली सप्लाई करने के लिए जिस तरह से यहां पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन है उसी तरह से विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन बना कर के उपभोक्ताओं को एक दर से और सस्ती दर से बिजली सप्लाई करने का विचार रखते है। इस के साथ-साथ मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और भाखरा प्रबन्ध बोर्ड के बीच में जो विवाद चल रहा है राशि की भुगतान के सम्बन्ध में उसका कब तक निर्णय करा देने का विचार रखते है ?

DR. K. L RAO : I did not know that the hon. Member would be interested in having the break-up of this sum of Rs. 6.5 crores. The claim has arisen on account of three points. The first is about the quantum of power. The Bhakra Management Board thinks that it is 60 MW while the DESU thinks that it should be 80 MW. The second one is about the rate. The Bhakra Management Board says that it should be 7 93 p Thile the DLSU says that it should be 4 3 p per unit. The third is about the the date. The Bhakra Management Board says that it should be 10th December, 1968 whereas the DESU says that it should be 1st April, 1970. These are the various points on which there is difference and that is how the money has come to about Rs. 6.5 crores. All these points will be gone into by the Ministry of Irrigation and Power ; as I have stated, the case was sent to them only about a fortnight

back, and it will take some time to verify the facts and then the necessary things will be done.

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : मैंने कारपोरेशन बनाने के बारे में पूछा था । कारपोरेशन बनाकर एक ही रेट पर दिल्ली के वास्ते विद्युत की आपूर्ति करने का क्या आप विचार रखते हैं ?

DR. K. L RAO : In regard to DESU reorganisation, proposals are under way, but it has not been decided as to what final shape it will take.

SHRI HARI KISHORE SINGH (Pupri) : When news appeared in the papers that the Bhakra Nangal Board has given notice to DESU to cut off electricity, we were quite sure that the Central Government would not permit it We are glad to have this assurance from the Minister that power will not be cut off But it definitely speaks ill of the administration that one public undertaking should be quarrelling with another for realisation of dues It is not only a question between these two departments, but between many other departments, we hear of such differences being aired in public. For example, we hear that the telephone department cut off the telephone connection of another department because of accumulation of dues ; this kind of thing puts both the public and the government machinery to great inconvenience. Are Government going to devise a machinery for solving such problems so that in future such public airing of such difference does not take place, and if there is a problem, it is automatically referred to a board which will resolve it by due process and there is no public fuss over it ?

Secondly, what would be the effect of the removal of disparity in power supply rates in various parts of Delhi ? If the Minister has not the information with him ready at hand, could he give it to us later ?

Thirdly, are there cases of this nature in other parts of the country where one public undertaking owes dues to another ? Also, are Government contemplating constitution of suitable machinery to resolve such problems ?

DR. K. L. RAO : There is no necessity to constitute a special machinery to dealing with such cases. There is sufficient provision in the Act for the purpose. Government have enough powers under the Act. The Bhakra Management Board will deal with it in terms of the Act. There is no necessity to create a special machinery.

As to the question whether there are similar differences in other parts of the country, there are bound to be. Every State Electricity Board supplying power has a claim on certain agencies. The Government of India have given a direction as to how these rates must be calculated and so on. In spite of that, there is always difference arising. For example, between MP and Orissa, there is a difference about the rates to be charged for the Hirakud power. I am trying to do my best with the Chief Ministers of both States. These are settled amicably without creating difficulty by way of cutting off power and so on.

As for the question of uniformity of rates all over Delhi, we have not taken up that subject because there are two agencies here, the NDMC and DESU. One or two hon. members have mentioned this to me I will take it up and see whether any kind of readjustment is required.

———

12 24 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE

EXPLANATION FROM EDITOR OF THE *Financial Express*, BOMBAY

MR. SPEAKER : Shri N K. Sanghi, M P , in his letter dated the 2nd April, 1972, had complained to me that the *Financial Express*, Bombay, in its issue dated the 1st April, 1972, had published two news items attributing them to the "Financial Express Bureau," although they were based on the information contained in answers to certain questions in the House. Shri Sanghi had contended that the said newspaper should have made a reference to the relevant Lok Sabha proceedings as the source of those news items.

The Editor of the *Financial Express*, Bombay, who was asked, under my direction, to state what he had to say in the matter, has